

Seema Kumari

Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, Sasaram

Topic - American Political System

Date - 03.05.2021

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था (समिति प्रणाली)

सदन नियमावली समिति (House Rules Committee)

यह भी की समिति यह निर्णय करती है कि किसी विधेयक को सदन में किस रूप में रखा जाय या नहीं? यह वाद विवाद के समय को भी निर्धारित करती है

कांग्रेस की विभिन्न समितियां विधि निर्माण के कार्य में सहायता देने के लिए बनाई जाती हैं ये समितियां समय समय पर प्रशासनिक विभागों की तरफ-तरफ की विवरण या जानकारी मांगती रहती हैं इस मामले में ऐसा अनुशासन विकसित किया गया है प्रशासनिक विभाग कांग्रेस समितियों की प्रवृत्तियों को महत्व देती हैं और अपेक्षित जानकारी या विवरण देने को हमेशा तैयार रहते हैं इससे कांग्रेस समितियों को प्रशासनिक विभागों के काम काण्ड के निरीक्षण का अवसर मिल जाता है संसदीय प्रणाली की तरह अमेरिका में संगठित विपक्ष काम नहीं करता है। प्रशासनिक विभागों पर कांग्रेस समितियों का निरीक्षण इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर देता है।

संघीय कार्यपालिका (Federal Executive)

अमेरिका में अद्यतनीय शासन प्रणाली है राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अद्यतन है। उसके नीचे उप-राष्ट्रपति है। वह अपनी कैबिनेट का निर्माण करता है जो कांग्रेस से चुक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। इन सबको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं

अमेरिका में स्थायी या अशासनिक कार्यपालिका भी है जिससे मौकशाही (Bureaucracy) की संज्ञा दी जाती है।

राष्ट्रपति

अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्तिशाली व सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति का है। अमेरिकी शासन प्रणाली के अंतर्गत शारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित रहती हैं। राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने के लिए शक्तिशाली होने व मनमानी करने से नियंत्रित करने के लिए अमेरिका में शक्ति पार्थक्य (Separation of powers), बॉर अवरॉथ व संतुलन (Check and Balances) की विस्तृत व्यवस्था की गई है।

कार्यकाल, उत्तराधिकार तथा निष्कासन

4 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। किसी व्यक्ति को दो बार से अधिक नहीं चुना जा सकता।

राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उप राष्ट्रपति उसका पदभार संभालेगा। उप राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होने पर उस व्यक्ति का जिसकी पुष्टि कांग्रेस के दोनों सदनों में होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का कोई गंभीर आरोप लगता है तो उसे महा-मिथोंग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। A.A की एक कमिटी आरोप पत्र तैयार करती है, यह मामला सीनेट के समक्ष रखी जाती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज करेगा। राष्ट्रपति को अपना बचाव का अधिकार होगा। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि द्वारा अपना बचाव कर सकता है। सीनेट में चर्चा होती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। उसके बाद देउ या निष्कासन की प्रक्रिया होती है।